

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021

पाठ्यक्रम: जीएस पेपर-II (महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समूह)

संदर्भ: हाल ही में, लोकसभा ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 पारित किया जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) के लिए एक वैधानिक ढांचा बनाने का प्रयास करता है।

केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संचालित, इसे पहली बार दिसंबर 2021 में लोकसभा में पेश किया गया था।

यह विधेयक खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करेगा क्योंकि यह उन्हें अपने संस्करणों को प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करेगा, खासकर जब वे डोपिंग रोधी आरोपों का सामना करते हैं।

विधेयक के प्रावधान

- टीवह बिल एथलीटों, एथलीट सहायता कर्मियों और अन्य व्यक्तियों को खेल में डोपिंग में शामिल होने से रोकता है।
- डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के परिणामस्वरूप परिणामों की अयोग्यता हो सकती है जिसमें पदक, अंक और पुरस्कारों की जब्ती, एक निर्धारित अवधि के लिए प्रतियोगिता या घटना में भाग लेने के लिए अयोग्यता, वित्तीय प्रतिबंध आदि शामिल हैं।
- विधेयक में इस राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी को एक सांविधिक निकाय के रूप में गठित करने का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक द्वारा की जाती है। एजेंसी के कार्यों में शामिल हैं:
 1. योजना, लागू करने, और विरोधी डोपिंग गतिविधियों की निगरानी,
 2. विरोधी डोपिंग नियम के उल्लंघन की जांच,
 3. विरोधी डोपिंग अनुसंधान को बढ़ावा देने.
- यह विधेयक डोपिंग रोधी विनियमन और डोपिंग रोधी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर सरकार को सिफारिशें करने के लिए खेलों में डोपिंग रोधी के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना करता है।
- बोर्ड एजेंसी की गतिविधियों की निगरानी करेगा और इसे निर्देश जारी करेगा।
- मौजूदा राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को प्रमुख डोप परीक्षण प्रयोगशाला माना जाएगा।
- केंद्र सरकार अधिक राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना कर सकती है।

बिल का महत्व

- यह विधेयक डोपिंग से लड़ने में एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने के अलावा एथलीटों के लिए समयबद्ध न्याय प्राप्त करने का प्रयास करता है।
- यह स्वच्छ खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करने का एक प्रयास भी है।
- यह बिल एंटी-डोपिंग निर्णय के लिए एक मजबूत, स्वतंत्र तंत्र स्थापित करने में मदद करेगा।
- यह विधेयक नाडा और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) के कामकाज को कानूनी पवित्रता प्रदान करेगा।

विधेयक के साथ मुद्दे

- महानिदेशक की अर्हताएं विधेयक में विनिदष्ट नहीं की गई हैं और उन्हें नियमों के माध्यम से अधिसूचित किए जाने के लिए छोड़ दिया गया है।
- केंद्र सरकार महानिदेशक को दुर्व्यवहार या अक्षमता या "इस तरह के अन्य आधार" के आधार पर कार्यालय से हटा सकती है।
- इन प्रावधानों को केंद्र सरकार के विवेक पर छोड़ने से महानिदेशक की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।
- यह विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के जनादेश के खिलाफ भी जाता है कि ऐसे निकायों को अपने संचालन में स्वतंत्र होना चाहिए।

- विधेयक के तहत, बोर्ड को अनुशासनात्मक पैनल और अपील पैनल के सदस्यों को इस आधार पर हटाने की शक्तियां हैं जो विनियमों द्वारा विनिदष्ट की जाएंगी और विधेयक में विनिदष्ट नहीं हैं।
- इसके अलावा, उन्हें सुनने का अवसर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह इन पैनलों के स्वतंत्र कामकाज को प्रभावित कर सकता है।

विश्व हेपेटाइटिस दिवस

सिलेबस: जीएस पेपर-II (स्वास्थ्य, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप)

विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल 28 जुलाई को वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।

वर्ष 2022 का विषय "हेपेटाइटिस देखभाल को आपके करीब लाना" है।

इसका उद्देश्य हेपेटाइटिस देखभाल को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के करीब लाने की आवश्यकता को उजागर करना है, और इसलिए समुदायों को उपचार और देखभाल तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए।

हेपेटाइटिस के बारे में

- हेपेटाइटिस शब्द यकृत की किसी भी सूजन को संदर्भित करता है - किसी भी कारण से जिगर की कोशिकाओं की जलन या सूजन।
- यह तीव्र हो सकता है (जिगर की सूजन जो बीमारी के साथ प्रस्तुत करती है - पीलिया, बुखार, उल्टी) या पुरानी (जिगर की सूजन जो छह महीने से अधिक समय तक रहती है, लेकिन कोई लक्षण नहीं दिखा रही है)।

कारण

- आमतौर पर वायरस के एक समूह के कारण होता है जिसे "हेपेटोट्रोपिक" (यकृत निर्देशित) वायरस के रूप में जाना जाता है, जिसमें ए, बी, सी, डी और ई शामिल हैं।
- अन्य वायरस भी इसका कारण बन सकते हैं, जैसे कि वैरिसेला वायरस जो चिकन पॉक्स का कारण बनता है।
- सार्स-कोव-2, कोविड-19 का कारण बनने वाला वायरस यकृत को भी घायल कर सकता है।
- अन्य कारणों में ड्रग्स और अल्कोहल का दुरुपयोग, जिगर में वसा बिल्डअप (फैटी लिवर हेपेटाइटिस) या एक ऑटोइम्यून प्रक्रिया शामिल है जिसमें किसी व्यक्ति का शरीर एंटीबॉडी बनाता है जो जिगर (ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस) पर हमला करता है।

हेपेटाइटिस एकमात्र संचारी रोग है जहां मृत्यु दर में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है।

उपचार

- हेपेटाइटिस ए और ई स्व-सीमित रोग हैं (यानी, अपने दम पर चले जाते हैं) और किसी विशिष्ट एंटीवायरल दवाओं की आवश्यकता नहीं होती है।
- हेपेटाइटिस बी और सी के लिए, प्रभावी दवाएं उपलब्ध हैं।

वैश्विक परिदृश्य

- लगभग 354 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी और सी से पीड़ित हैं।
- दक्षिण पूर्व एशिया में हेपेटाइटिस के वैश्विक रुग्णता बोझ का 20% है।
- हेपेटाइटिस से संबंधित सभी मौतों में से लगभग 95% हेपेटाइटिस बी और सी वायरस के कारण सिरोसिस और यकृत कैंसर के कारण होती हैं।

भारतीय परिदृश्य

- वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस वायरस ए के माध्यम से ई के कारण होता है, भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है।
- भारत में हेपेटाइटिस बी सतह एंटीजन के लिए "मध्यवर्ती से उच्च स्थानिकता" है और अनुमानित 40 मिलियन क्रोनिक एचबीवी संक्रमित लोग हैं, जो अनुमानित वैश्विक बोझ का लगभग 11% है।
- भारत में क्रोनिक एचबीवी संक्रमण की जनसंख्या का प्रसार लगभग 3-4% है।

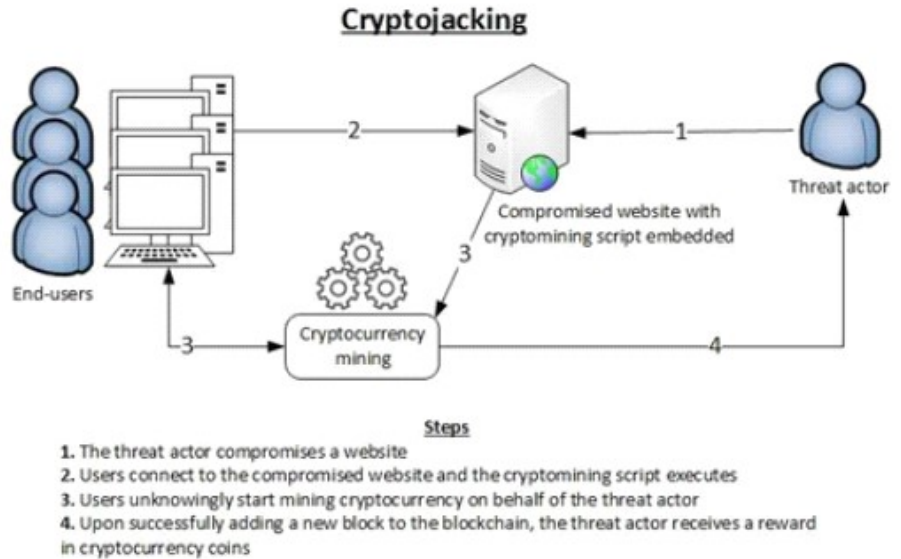
चुनौतियों

- स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच अक्सर समुदायों के लिए पहुंच से बाहर होती है क्योंकि वे केंद्रीकृत / विशेषीकृत अस्पतालों में एक लागत पर उपलब्ध होती हैं जो सभी द्वारा वहन नहीं की जा सकती हैं।
- देर से निदान या उचित उपचार की कमी के कारण लोग मरना जारी रखते हैं। प्रारंभिक निदान रोकथाम और सफल उपचार दोनों के लिए प्रवेश द्वार है।
- दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में, हेपेटाइटिस वाले केवल 10% लोग अपनी स्थिति जानते हैं; और उनमें से, केवल 5% उपचार पर हैं।
- हेपेटाइटिस सी वाले अनुमानित 10.5 मिलियन लोगों में से, केवल 7% अपनी स्थिति जानते हैं, जिनमें से पांच में से लगभग एक उपचार पर है।

प्रारंभिक परीक्षा मुख्य तथ्य

प्रतिस्थापन स्तर उर्वरता प्राप्त

- भारत ने 31 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता प्राप्त की है, जो 2.1 या उससे कम की कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या) तक पहुंच गई है।
- प्रतिस्थापन स्तर की उर्वरता प्रजनन क्षमता का वह स्तर है जिस पर एक जनसंख्या वास्तव में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में खुद को बदल देती है, अर्थात्, पीढ़ी दर पीढ़ी जनसंख्या को समान रखने के लिए आवश्यक प्रजनन क्षमता का स्तर।
- सरकारी आंकड़ों ने अंतराल के तरीकों की ओर एक समग्र सकारात्मक बदलाव दिखाया जो सकारात्मक रूप से मातृ और शिशु मृत्यु दर और रुग्णता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम अब सात दशकों से अधिक पुराना है, और इस अवधि में, देश ने जनसंख्या नियंत्रण की अवधारणा से जनसंख्या स्थिरीकरण की अवधारणा से लेकर निरंतरता देखभाल के सद्भाव को सुनिश्चित करने की दिशा में अंतर्निहित हस्तक्षेपों के लिए एक प्रतिमान परिवर्तन देखा था।



क्रिप्टो जैकिंग

- एक रिपोर्ट के अनुसार, कंप्यूटर सिस्टम पर क्रिप्टो जैकिंग हमले पिछले साल की पहली छमाही की तुलना में 2022 की पहली छमाही में 30% बढ़कर 66.7 मिलियन हो गए हैं।
- क्रिप्टो जैकिंग एक साइबर-हमला है जिसमें एक कंप्यूटिंग डिवाइस को हमलावर द्वारा अपहृत और नियंत्रित किया जाता है और इसके संसाधनों का उपयोग क्रिप्टोक्यूरेंसी को अवैध रूप से खनन करने के लिए किया जाता है।
- ज्यादातर मामलों में, दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम स्थापित किया जाता है जब उपयोगकर्ता एक असुरक्षित लिंक पर क्लिक करता है, या एक संक्रमित वेबसाइट पर जाता है - और अनजाने में अपने इंटरनेट से जुड़े डिवाइस तक पहुंच प्रदान करता है।
- क्रिप्टो जैकिंग का पता लगाना मुश्किल है और इन हमलों के पीड़ित ज्यादातर अनजान रहते हैं कि उनके सिस्टम से समझौता किया गया है। कुछ संकेत डिवाइस को धीमा कर रहे हैं, हीटिंग अप कर रहे हैं या बैटरी सामान्य से अधिक तेजी से सूखा हो रही है।

संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA)

- भारत ने निकट पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) को \$ 2.5 मिलियन का योगदान दिया।
- यह 1949 में लगभग 5.6 मिलियन फिलिस्तीनी शरणार्थियों (वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन में) को सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के जनादेश के साथ स्थापित किया गया था।
- **वित्त पोषण:** केवल स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से।
- **लिंक वेस्ट नीति** के एक हिस्से के रूप में, भारत ने 2018 में इजरायल और फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों को डी-हाइफ्रनेट किया है ताकि दोनों देशों को पारस्परिक रूप से स्वतंत्र और अनन्य माना जा सके।

विदेशी संपत्ति मामलों की जांच के लिए मल्टी एजेंसी समूह

- भारत सरकार ने विदेशी परिसंपत्ति मामलों की जांच के लिए एक "मल्टी-एजेंसी समूह" की स्थापना की है।
- इस समूह में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों और संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसकी अध्यक्षता **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)** के अध्यक्ष करेंगे।
- यह विदेशी संपत्ति के मामलों की विभिन्न श्रेणियों की जांच में शामिल होगा जैसे कि **पीरेडिस पेपर लीक, पनामा पेपर लीक, और पेंडोरा पेपर लीक**।
- **इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट (आईसीआईजे)** ने अक्टूबर 2021 में जारी एक खोजी रिपोर्ट (पेंडोरा पेपर) में दावा किया कि 380 भारतीय वैश्विक अभिजात वर्ग की सूची में हैं, जिन्हें छायादार वित्तीय लेनदेन के माध्यम से अपनी संपत्ति को रिंग-फेंसिंग करने और लाखों डॉलर की संपत्ति को छिपाने के लिए अपतटीय कर स्वर्ग का उपयोग करने के लिए उजागर किया गया है।

